

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3076/2018

1. मेसर्स कुबेर ट्रेडिंग कंपनी (एक प्रोप्राइटरी फर्म जिसका कार्यालय 9/सी, मंडी यार्ड, बिजय नगर, जिला अजमेर में है) अपने एकमात्र प्रोप्राइटर प्रसन्न कुमार जैन पुत्र श्री पारसमल चतर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी चतरों का मोहल्ला, भिनाई, तहसील भिनाई, जिला अजमेर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. प्रसन्न कुमार जैन पुत्र श्री पारसमल चतर, (मेसर्स कुबेर ट्रेडिंग कंपनी याचिकाकर्ता संख्या 1 के प्रोप्राइटर), उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी चतरों का मोहल्ला, भिनाई, तहसील भिनाई, जिला अजमेर (राजस्थान)।
3. पारसमल चतर पुत्र स्वर्गीय श्री रतन लाल महाजन, जो दिवंगत हो चुके हैं, कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से :
 - 3/1. श्रीमती संतोष देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री पारसमल चतर, निवासी चतरों का मोहल्ला, भिनाई, तहसील भिनाई, जिला अजमेर (राजस्थान)।
 - 3/2. श्रीमती प्रियदर्शिनी बाबेल पत्नी दीपक बाबेल, पुत्री स्वर्गीय श्री पारसमल चतर, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 902, क्रिमसन टावर, कांदीवाली (ई) मुंबई (महाराष्ट्र)।
 - 3/3. पारसन कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय श्री पारसमल चतर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी चतरों का मोहल्ला, भिनाई, तहसील भिनाई, जिला अजमेर (राजस्थान)।
 - 3/4. श्रीमती सोनिका सांड पत्नी संदीप सांड, पुत्री स्वर्गीय श्री पारसमल चतर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी पाली, सी/ओ क्रिस्टल लाइट्स एंड डेकोर, अंबेडकर नगर, पाली (राजस्थान)।
 - 3/5. सुप्रिया पुत्री स्वर्गीय श्री पारसमल चतर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी चतरों का मोहल्ला, भिनाई, तहसील भिनाई, जिला अजमेर (राजस्थान)।

---अपीलकर्ता-आवेदक/याचिकाकर्ता।

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक अपने शाखा प्रबंधक, शाखा बिजय नगर, जिला अजमेर (राजस्थान) के माध्यम से।

---गैर-अपीलकर्ता/गैर-आवेदक-प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता की ओर से:

श्री सारांश सैनी, अधिवक्ता, श्री
संजीव कुमार, अधिवक्ता के साथ।

प्रतिवादी की ओर से:

श्री दिनेश गर्ग, अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

आदेश

07/03/2024

- यह याचिका ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद 'अपीलीय न्यायाधिकरण') द्वारा पारित 08.01.2018 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को वसूल किए जाने वाले ऋण का 50% जमा करने का निर्देश दिया गया था।
- संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-बैंक से नकद ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं और ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए दुकान को गिरवी रखा गया था। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहने पर खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। वसूली की कार्यवाही शुरू की गई और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (इसके बाद 'डीआरटी') ने 04.03.2013 के आदेश के माध्यम से ₹23,46,353/- को 14.75% प्रति वर्ष की दर से मासिक शेष के साथ लंबित वाद और भविष्य के ब्याज के साथ वसूल करने योग्य माना। डीआरटी के आदेश को अंतिम रूप दिया गया। याचिकाकर्ता ने निष्पादन कार्यवाही में आपत्तियां दायर कीं और अस्वीकृति पर, डीआरटी से संपर्क किया। 07.12.2015 को अपील खारिज होने पर, याचिकाकर्ता ने ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 (इसके बाद '1993 का अधिनियम')

की धारा 21 के तहत एक आवेदन के साथ अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें पूर्व-जमा की छूट मांगी गई। गिरवी रखी गई दुकान की ₹21,87,000/- में नीलामी की गई। छूट के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.02.2017, 23.05.2017 और 19.08.2017 के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ₹5,90,000/- जमा किए। यह भी तर्क दिया गया कि बैंक ने गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करके ₹21,87,000/- की वसूली की थी। उनका तर्क है कि अपील को बिना किसी और जमा के सुना जाने का आदेश दिया जाए।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने नीलामी की कार्यवाही को चुनौती दी है और मामला डीआरटी के समक्ष विचाराधीन है। वह निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं थी और नीलामी क्रेता के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया गया है।

5. 1993 के अधिनियम की धारा 20 (1) किसी व्यक्ति द्वारा डीआरटी द्वारा दिए गए या दिए गए माने गए आदेश से व्यथित होने पर अपीलीय प्राधिकरण में अपील का प्रावधान करती है। इसका अपवाद उन आदेशों को छोड़कर है जो धारा 2 के तहत आते हैं।

6. धारा 21 निम्नानुसार है:

“अपील दायर करने पर देय ऋण की राशि का जमा।

जहां किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे बैंक या वित्तीय संस्थान या बैंकों या वित्तीय संस्थानों के एक संघ को ऋण की राशि देय है, एक अपील दायर की जाती है, ऐसी अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने न्यायाधिकरण द्वारा धारा 19 के तहत निर्धारित किए गए ऋण की राशि का पचास प्रतिशत अपीलीय न्यायाधिकरण के पास जमा नहीं कर दिया हो:

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इस धारा के तहत जमा की जाने वाली ऐसी ऋण की राशि के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होने वाली राशि को जमा करने के लिए कम कर सकता है।”

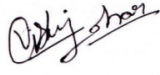
7. धारा 21 के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे राशि देय है, अपील को डीआरटी द्वारा निर्धारित किए गए देय ऋण की राशि के 50% की पूर्व-जमा के बिना अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. परंतुक के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पूर्व-जमा राशि को 25% तक कम कर सकता है।
9. डीआरटी के आदेश के अनुसार देय ऋण ₹23,46,353/- और उस पर ब्याज था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता द्वारा ₹5,90,000/- की राशि पहले ही जमा की जा चुकी है और बैंक ने गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करके ₹21,87,000/- की राशि प्राप्त की है। दूसरे शब्दों में, देय ऋण के 50% से अधिक की वसूली हुई है, परिणामस्वरूप, चुनौती दिए गए आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलीय न्यायाधिकरण को बिना किसी और जमा के योग्यता के आधार पर अपील सुनने का निर्देश दिया जाता है।
10. यह देखते हुए कि अपील 2016 से लंबित है, अपीलीय न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों में यथासंभव शीघ्रता से अपील का निपटान करने का एक गंभीर प्रयास करेगा। आगे की देरी से बचने के लिए, पक्ष 08 अप्रैल, 2024 को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।
11. याचिका स्वीकार की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/108

रिपोर्ट करने योग्य:- हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़